environment, particularly in the urban areas of the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the measures being taken by Government to tackle this menace?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) The articles of non-degradable plastic material left as litter, are not creating havoc to the environment, as these are being recycled and reused.

वृक्षारोपण

2440. **श्री रामजीलाल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा कितने वृक्ष लगाये गये हैं, उनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं और कितने सूख गये हैं, उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन-वर्षों के दौरान और वर्ष 1995-96 में इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन पेड़ों के सूखने के कारणों के बारे में कोई जांच करायी है; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वनरोपण के संबंध में सरकार की नीति क्या है और उनके परिणामस्वरूप प्रदूषण में किस सीमा तक कमी आयी है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य-कलाप केन्द्र तथा राज्य योजनाओं में उपलब्ध धनराशि के आधार पर सारे देश में चलाए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वनीकरण के लिए निर्धारित राज्य-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं। (देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 54)

देश भर में चयनित 50 जिलों में किए गए नमूना जांच के आधार पर वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवर्ष जीवितता दर आकलन किए जाते हैं। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य-कलापों के संबंध में किए गए नमूना जांच पूरे कर लिए गए हैं। 1993-94 के दौरान किए गए वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों की नमूना जांच की जा रही है। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के नमूना जांच के नतीजे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। (नीचे देखिए) इन नमूना जांचों से पता चलता है कि स्थान-वार और प्रजाति-वार भिन्नता को देखते हुए वृक्षारोपण की समग्र जीवितता दर आमतौर पर 55% से 80% के बीच रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में केन्द्र और राज्य योजना निधि से सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ रखी गई कुल धनराशि का प्रावधान निम्न प्रकार है:

वर्ष	लाख रुपए
1991-92	75198.96
1992-93	79288.02
1993-94	90177.44

+(अनंतिम)

वर्ष 1995-96 के आवंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) तथा (घ) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य-कलापों की निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी-अपनी व्यवस्थाएं हैं। वनीकरण कार्यक्रम के तहत लगाई गई पौद कई कारणों से नष्ट हो जाती है, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, जैविक दबाव विशेषकर आवारा पशुओं द्वारा चराई, रोग, कठिन मृदीय परिस्थितियां आदि। राज्य सरकारें उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करती हैं जो लगाई गई पौध को क्षति पहुंचाने के लिए दोषी पाए जाते हैं।

(ङ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 अवक्रमित वन-क्षेत्रों का सुधार करके, निजी, सामुदायिक तथा अन्य भूमियों पर वृक्षारोपण करके व कृषि-वानिकी चलाकर देश के कुल भूमि-क्षेत्र के कम से कम एक-तिहाई क्षेत्र को वनावरण/वृक्षावरण के अन्तर्गत लाए जाने और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को शामिल करके एक व्यापक जन-आंदोलन चलाए जाने पर बल देती है। चूंकि वृक्ष प्रकाश-संश्लेषण क्रिया से आक्सीजन

छोड़ते हैं और कार्बन-डाइ-आक्साइड लेते हैं अतः अवक्रमित वनों का सुधार/वृक्षारोपण, समग्र रूप में प्रदूषण कम करने में मददगार साबित होता है।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 के दौरान किए गए वृक्षारोपण के संबंध में स्वतंत्र विशेषज्ञों/एजेंसियों द्वारा किए गए जीवितता दर अध्ययनों के नतीजे

क्र० सं०	जिले का नाम	औसत जीवितता प्रतिशत*
1.	पश्चिम त्रिपुरा	70.6%
2.	पश्चिम कामेंग	80.3%
3.	पश्चिम खासी पहाड़ियां	65.8%
4.	मेहसाना	70.0% और उससे ऊपर
5.	कोरापुट	85.0%—90.0%
6.	मण्डी	78.34%
7.	अलवर	88.22%
8.	संगरूर	86.4%
9.	जालौन	82.85%
10.	बरेली	74.25%
11.	सरगुजा	75.48%
12.	जोरहाट	40.0—50.0%
13.	मोकोकचुंग	80.0%—90.0%
14.	मणीपुर	70.0%—80.0%
15.	बहराईच	85.2%
16.	चन्द्रपुर	64.5%
17.	छिन्दवाड़ा	61.3%
18.	कपूरथला	91.7%
19.	मिदनापुर	49.2%
20.	नादिया	79.6%
21.	सम्बलपुर	81.4%
22.	दक्षिण सिक्किम	50.6%
23.	मेडक	62.8%
24.	गोवा	68.0%
25.	इटुकी	71.78%
26.	कासरगोड	84.83%
27.	जलगांव	77.71%
28.	तंजावुर	81.2%
29.	पूर्व गोदावरी	68.28%
30.	कथुआ	62.17%
31.	कोलार	70%—90%
32.	बस्तर	82.07%
33.	पौड़ी गढ़वाल	77.72%
34.	जामनगर	70% और उससे ऊपर
35.	बाड़मेर	72.0%
36.	मंदसौर	51.43%
37.	चुरू	72% से 87% तक
38.	डूंगरपुर	65% से 85% तक
39.	भिवानी	60% से 98% तक
40.	बेल्लौर	82.7%
41.	नीलगिरि	70% से 90% तक
42.	गुलबर्गा	22%
43.	मंगलौर (दक्षिण कनड़)	87%
44.	धर्मपुरी	69%

*प्रजाति-वार/स्थान-वार भिन्नता के आधार पर।

विवरण-II

वर्ष 1992-93 के दौरान किए गए वृक्षारोपण के संबंध में स्वतंत्र विशेषज्ञों/एजेंसियों द्वारा किए गए जीवितता दर अध्ययनों के नतीजे

क्र० सं०	जिले का नाम	औसत जीवितता प्रतिशत*
1.	महबूब नगर	67.17
2.	त्रिसौर	44.53
3.	शिमोगा	67.39
4.	खम्माम	63.73
5.	होशंगाबाद	72.34
6.	क्वीलोन	84.78
7.	बरान	79.00
8.	बीकानेर	68.25
9.	उदयपुर	72.75
10.	सिंहभूम	84.85
11.	जलपाईगुड़ी	55.5
12.	धूले	74.92
13.	पश्चिम सिक्किम	51.13
14.	सलेम	72.5
15.	पूर्वी खासी पहाड़ियां	59.5
16.	पश्चिम मणिपुर	79.7
17.	पश्चिम त्रिपुरा	73.3
18.	कार्बी अंगलौंग	60
19.	ऐजवाल	55 से 65 तक
20.	कोहिमा	70 से 80 तक
21.	प० सियांग	60 से 70 तक
22.	फूलबनी	85 से 95 तक
23.	उत्तरी आरकोट	84
24.	पेरियार	79
25.	चम्बा	59.48
26.	रोहतक	83.6
27.	भटिंडा	80
28.	अम्बाला	67 से 78 तक
29.	होशियारपुर	62 से 86 तक

क्र. सं.	जिले का नाम	औसत जीवितता प्रतिशत*
30.	गोरखपुर	63.31
31.	गिरीडीह	60
32.	गिरीडीह	65
33.	गिरीपुरी	78.4
34.	गुडहपा	60
35.	गूनागढ़	70.8
36.	गयाना	65.93
37.	हमीरपुर	82.1
38.	हुगलिया	0 से 90 तक
39.	पश्चिम चम्पारन	82
40.	जिरयौर	67.17
41.	खुदरगढ़	86.7
42.	ढेंकनाल	80 से 93 तक
43.	कोरेयापुर	85
44.	बिलासपुर	75

*प्रजाति-वार/स्थान-वार भिन्नता के आधार पर।

Proposal for environmental and forest clearance

2441. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Union Government have received any proposals for environmental as well as forest clearance from Governments of Rajasthan and Orissa, during 1993—96;

(b) if so, the action taken thereon, year-wise;

(c) the names of similar other proposals from the above States, pending with his Ministry for the last three years, year-wise and State-wise; since which date these have been pending and the reasons therefor; and

(d) what steps have been taken, till date to clear such proposals; the cost of escalation involved in each cases and any target date fixed therefor, till date?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A statement showing the status of the proposals is enclosed *(See* below). As soon as complete details are received from the State Government's proposals are processed expeditiously for clearance from environment and forests angles.

Statement

Year		Pending with State Government		Approved in Principle		Rejected		Pending with Central Government		Total
		Forest	Environ-ment	Forest	Environ-ment	Forest	Environ-ment	Forest	Environ-ment	
1993	Rajasthan	2	1			1				
	Orissa		1	7				4		13
1994	Rajasthan	2	1					3		
	Orissa	5	4	1		1				19
1995 (Till 28.2.1995)	Rajasthan							2		
	Orissa									1

Denotification of the forest and national park areas

2442. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have been denotifying fully and /or partially, the protected forest and national park areas from time to time;

(b) if so, the details of areas so denotified since 1990-91; and